दैनिक जागरण iNext

एनएसआई, आईआईटी मिलकर तैयार करेंगे...
बायोफ्यूल की नेक्स्ट जेनरेशन

एविएशन फ्यूल, कास्ट कटिंग, बाई प्रोडक्ट का यूज, समेत कई टॉपिक्स पर होगी स्टडी

kanpur@inext.co.in

KANPUR (15 June): नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) कानपुर मिलकर बायोफ्यूल की नेक्स्ट जेनरेशन को तैयार करेंगे. इस काम के लिए सैटरडे को एनएसआई और आईआईटी के बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) फॉर बायो फ्यूल्स पर एमओयू हुआ. आईआईटी डायरेक्टर डॉ. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि इस सेंटर में दोनों संस्थान मिलकर बायोफ्यूल की नेक्स्ट जेनरेशन को यूज के लायक बनाएंगे. इसके अलावा पूरे स्पेक्ट्रम में साइंस से लेकर यूजर के पास तक ले जाने के लिए काम करेंगे.

सीएनजी में मिलाएंगे सीबीजी

एमओयू पर ज्वाइंट सेक्रेटरी (शुगर) भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण अश्वनी श्रीवास्तव, आईआईटी डायरेक्टर डॉ. मणींद्र अग्रवाल और एनएसआई डायरेक्टर प्रो. सीमा परोहा ने साइन किए. एमओयू के बाद सीओई की लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया गया. ज्वाइंट डायरेक्टर (शुगर) अश्वनी श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले कल में सीएनजी में कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) को कुछ मात्रा में मिलाया जाएगा. सीबीजी का प्रोडक्शन शुगर मिल्स में किया जाएगा.

20 परसेंट इथेनॉल का टारगेट

बताया कि अभी हम पेट्रोल में 12 परसेंट इथेनॉल को मिला रहे हैं. 2025 तक 20 परसेंट मिलाने का टारगेट है. इस टारगेट को पूरा करने के लिए सीओई में काम किया जाएगा. पेट्रोल में जितना ज्यादा इथेनॉल को मिलाया जाएगा. उतना ईंपोर्ट कम करना पड़ेगा.

दोनों संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल्स के लिए एमओयू

PICS: DAINIK JAGRAN INEXT

आईआईटी में बायो फ्यूल्स पर एमओयू

इन पर होगी स्टडी

एनएसआई डायरेक्टर प्रो. सीमा परोहा ने बताया कि इस सेंटर में बायोमास के इथेनॉल, मीथेनॉल, सीबीजी, एविएशन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन आदि के डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा. इसके अलावा कास्ट कटिंग, बाई प्रोडक्ट का यूज और एनवायरमेंट पर पड़ने वाले इफेक्ट समेत कई पहलुओं पर स्टडी की जाएगी. इस काम के लिए सीओई में पायलट प्लांट, आवश्यक उपकरण और माडर्न लैब को स्थापित किया जाएगा. इस काम में खर्च होने वाले बजट को मिनिस्ट्री की ओर से दिया जाएगा, जिसकी स्वीकृति दी जाएगी.

वेस्ट से वेल्थ पर दिया जाएगा ध्यान

इस सेंटर में बायोफ्यूल्स के निर्माण में वेस्ट से वेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा. इसका सीधा सा मतलब है कि शुगर मिल्स से निकलने वाले वेस्ट को यूज बायोफ्यूल्स में किस तरह से कर सकते हैं. इस पर भी काम होना है. बताते चलें कि एनएसआई डायरेक्टर प्रो. सीमा परोहा ने शुगर मिल्स के निकलने वाले प्रेसमेड (वेस्ट) से सीएनजी बनाने पर रिसर्च की है, जिसमें सक्सेस मिली है.

CONCEPT PIC

इसके अलावा कार्बन एमीशन में भी कमी आएगी. आने वाले कल में फ्लेक्सी फ्यूल वाले व्हीकल आने वाले हैं. जो कि 100 परसेंट इथेनॉल से चलेंगे. कहा कि गन्ना आधारित फीड स्टॉक की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्के को एक प्रमुख फीड स्टॉक के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है.

यह है मॉनिटरिंग कमेटी

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होने वाले काम के लिए एग्जीक्यूटिव और मॉनीटरिंग कमेटी को बनाया गया है. इस कमेटी में एनएसआई डायरेक्टर प्रो. सीमा परोहा, आईआईटी के प्रो. राजीव जिंदल, आईआईटी के प्रो. देवोपम दास, विनय कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर, शुगर इंजीनियरिंग एनएसआई), अनूप कुमार कनौजिया (असिस्टेंट प्रोफेसर, शुगर इंजीनियरिंग एनएसआई) और डॉ. अनंतलक्ष्मी रघुनाथन शामिल हैं.

आज

आज महानगर

जैव ईंधन क्षेत्र में मिलकर शोध करेंगे एनएसआई और आईआईटी

तीन वर्षों के लिए करार, ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन पर अध्ययन करेंगे

कानपुर, 15 जून। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच एमओयू साइन किया गया। इस के तहत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में एक अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत सरकार, (शर्करा), संयुक्त सचिव अश्वनी श्रीवास्तव, आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल, एनएसआई की निदेशक प्रो. सीमा परोहा की मौजूदगी रही। इस अवसर पर आईआईटी के प्रो. राजीव जिंदल, प्रो. देवोपम दास तथा एनएसआई के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. (श्रीमती) आर. अनंतलक्ष्मी उपस्थित रहे। समझौता ज्ञापन के तहत एनएसआई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर 'देश में बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु, उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे। इस सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन तीन वर्षों के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर, दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। आईआईटी के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि एनएसआई इस संबंध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है। इसी प्रकार आईआईटी के पास रसायन एवं अन्य संबंधित तकनीकों में असाधारण क्षमता है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहयोग करने के लिए अत्याधुनिक विशिष्ट केंद्र निर्मित किए जाने हेतु दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करना है। एनएसआई, के निदेशक प्रो. सीमा परोहा ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल लागत राशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए पहले ही मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह 'समझौता ज्ञापन', नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उच्च, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने, कार्बन डाइऑक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुये जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता,कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा।

समझौता पत्र दिखाते आईआईटी निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल, संयुक्त सचिव अश्वनी श्रीवास्तव व एनएसआई की निदेशक प्रो. सीमा परोहा।

2025 तक इथेनाल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य, मक्के से इथेनाल उत्पादन पर जोर

कानपुर। भारत सरकार, (शर्करा), संयुक्त सचिव अश्वनी श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। गन्ना के अलावा अब इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्के को एक प्रमुख फीडस्टॉक के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इथेनॉल के अलावा, गन्ने के अन्य उप उत्पादों जैसे मोलैसेस से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) के उर्वरक, संपीडित बायो-गैस(सीबीजी) के रूप में प्रयोग के लिए, जिसे हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इनके उपयोग को बढ़ावा देकर वेस्ट से वैल्थ (व्यर्थ से अर्थ) की संकल्पना पर भी ध्यान दे रही है।जैव ईंधन की दीर्घकालिकता को ध्यान में रखते हुए इन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने से न केवल कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी बल्कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम होगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा।

अमर यात्रा

एनएसआई और आईआईटी बायो फ्यूल के क्षेत्र में राष्ट्र को बनाएंगे आत्मनिर्भर

अमर यात्रा ब्यूरो

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने 15 जून, 2024 को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में एक अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर श्री अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुए। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबाशीष दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के श्री विनय कुमार, श्री अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. (श्रीमती) आर. अनंतलक्ष्मी उपस्थित रहे।

समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर 'देश में बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु, उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे'। इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से प्रस्ताव लिये जायेंगे। अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों / विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों / उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे। इस सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनॉल, मीथेनॉल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

यह समझौता ज्ञापन तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर, दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है।

प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी कानपुर ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर इस संबंध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है। इसी प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पास रसायन एवं अन्य संबंधित तकनीकी में आधारभूत क्षमता है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहयोग करने के लिए अत्याधुनिक विशिष्ट केंद्र निर्मित किए जाने हेतु दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करना है।

श्री अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20%मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।

यह 'समझौता ज्ञापन', नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने, कार्बन डाइऑक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुये जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता/कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा।

भारत संवाद

एन एस आई व आई आई टी कानपुर जैव ईंधन तकनीक में विकास के लिए मिलाया हाथ

भारत संवाद

विशाल सैनी/कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और आइआइटी कानपुर ने जैव ईंधन तकनीक विकास के लिए हाथ मिलाया है। आइआइटी निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल और एनएसआइ की ओर से भारत सरकार के संयुक्त सचिव (शर्करा) अश्वनी श्रीवास्तव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइआइटी निदेशक ने बताया कि संस्थान के पास पहले से तकनीकी दक्षता है अब एनएसआइ के शोध निष्कर्षों का प्रयोग कर अगली पीढ़ी की जैव ईंधन तैयार करेंगे। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू के बाद एनएसआइ में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन अतिथियों ने किया। संयुक्त सचिव अश्वनी श्रीवास्तव ने बताया कि एथेनाल उत्पादन में भारत ने लक्ष्यों को पूरा किया है। इस साल 15 हजार करोड़ लीटर एथेनाल का उत्पादन हुआ है। अगले साल इसे 17 हजार करोड़ लीटर करने का लक्ष्य है। प्रोफेसर सीमा परोहा निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण,पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन,सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा।इसकी कुल लागत राशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी,जिसके लिए पहले ही मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

Times of India

IIT-K, NSI to develop Centre of Excellence for biofuels

TIMES NEWS NETWORK

Kanpur: The Indian Institute of Technology Kanpur (IIT-K) and National Sugar Institute, Kanpur (NSI) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to establish a Centre of Excellence for biofuels.

The MoU was signed on Saturday (June 15) in the presence of joint secretary (Sugar), department of food & public distribution, govt of India Ashwini Srivastava, director, IIT-K prof Manindra Agrawal, and director, NSI Kanpur Seema Paroha.

Under this MoU, IIT-Kanpur and NSI Kanpur will engage in the joint projects to conduct cutting-edge research and develop and adopt state-of-the-art technology to enhance biofuel production in the country.

Prof Manindra Agrawal said, "NSI Kanpur has been working in this field for over 60 years, understanding the market dynamics and technological requirements well while IIT Kanpur possesses the understanding of fundamental science and technologies. The aim is to combine the strengths of both institutions to create a state-of-the-art center."

Ashwini Srivastava said, "The National Bio-fuel policy, 2018 allows the production of ethanol from various sugarcane-based feedstock as well as use of surplus food grains for production of ethanol. Under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, the government has fixed the target of 20% blending of ethanol with petrol by 2025. The govt has been promoting maize as a major feedstock for production of ethanol. It is also focusing towards Waste to Wealth approach by promoting the usage of other by-products of sugarcane."

Dr Seema Paroha said, "A dedicated building with a state-of-the-art laboratory, including all requisite equipment, pilot plants, and instruments, will be established for the CoE at the institute campus. This will initially be funded by the ministry, and moving forward, industrial tie-ups will also be targeted."

आज

जैव ईंधन पर शर्करा संस्थान और आईआईटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर

आज का कानपुर

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने 15 जून, 2024 को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में एक अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय- जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुए। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर. अनंतलक्ष्मी उपस्थित रहे। समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर 'देश में बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए, संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे'। इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से प्रस्ताव लिये जायेंगे। अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों / विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों / उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे। इस सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से इथेनॉल, मीथेनॉल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

यह समझौता ज्ञापन तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर, दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है। प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी कानपुर ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर इस संबंध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है। इसी प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पास रसायन एवं अन्य संबंधित तकनीकों में आधारभूत क्षमता है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहयोग करने के लिए, अत्याधुनिक विशिष्ट केंद्र निर्मित किए जाने हेतु दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करना है। अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। गन्ना आधारित फीड-स्टाक की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश में इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्के को एक प्रमुख फीडस्टॉक के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

इथेनॉल के अलावा, गन्ने के अन्य उप उत्पादों जैसे मोलेसेस से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) के उर्वरक, संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) के रूप में प्रयोग के लिए, जिसे हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, सरकार इनके उपयोग को बढ़ावा देकर वेस्ट से वैल्थ (व्यर्थ से अर्थ) की संकल्पना पर भी ध्यान दे रही है। जैव ईंधन की दीर्घकालिकता को ध्यान में रखते हुए उन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने से न केवल कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी बल्कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम होगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा। केंद्र सुरक्षा एवं दीर्घकालिकता सुनिश्चित करते हुए जैव ईंधन नवाचार का समर्थन करेगा। उन्होंने दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच संयुक्त शोध कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएँ दीं। प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल लागत राशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए पहले ही मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह 'समझौता ज्ञापन', नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने, कार्बन डाइऑक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुये जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता/कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा।

दिनार टाइम्स

'जैव ईंधन के उत्कृष्टता केंद्र' के लिए आईआईटी व एनएसआई ने हाथ मिलाया

डीटीएनएन | कानपुर

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने 15 जून, 2024 को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में एक अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय- 'जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र' (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुए। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. (श्रीमती)आर. अनंतलक्ष्मी उपस्थित रहे। प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी कानपुर ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर इस संबंध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस

क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है। इसी प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पास रसायन एवं अन्य संबंधित तकनीकों में आधारभूत क्षमता है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहयोग करने के लिए अत्याधुनिक विशिष्ट केंद्र निर्मित किए जाने हेतु दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करना है। अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20%मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। गन्ना आधारित फीड-स्टाक की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश में इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्के को एक प्रमुख फीडस्टॉक के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इथेनॉल के अलावा, गन्ने के अन्य उप उत्पादों जैसे मोलेसेस से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) के उर्वरक, संपीड़ित बायो-गैस(सीबीजी) के रूप में प्रयोग के लिए, जिसे हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, सरकार इनके उपयोग को बढ़ावा देकर वेस्ट से वैल्थ (व्यर्थ से अर्थ) की संकल्पना पर भी ध्यान दे रही है।जैव ईंधन की दीर्घकालिकता को ध्यान में रखते हुए उन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने से न केवल कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी बल्कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम होगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा।

राष्ट्रिय सहारा

महानगर

कानपुर

5

शर्करा संस्थान व आईआईटी में बायो फ्यूल्स को लेकर एमओयू

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 15 जून को महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। समझौते में हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणीद्र अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की उपस्थिति में संपन्न हुए।

इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर. अनंतलक्ष्मी आदि उपस्थित रहे।

समझौता के अनुसार अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश में बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु उत्कृष्ट अनुसंधान, अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे। इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रस्ताव लिये जायेंगे। अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों /विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों /उद्योगों

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के साथ एमओयू करते आईआईटी निदेशक प्रो.मणींद्र अग्रवाल।

से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे। इस सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से एथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यह

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स केन्द्र स्थापित किया जायेगा

समझौता ज्ञापन तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है। प्रोफेसर मणीद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इस संबध में बाजारगत स्थिति और तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षो से कार्यरत है। इसी प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पास रसायन और अन्य संबंधित तकनीकी में आधारभूत क्षमता है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहयोग करने के लिए अत्याधुनिक विशिष्ट केंद्र निर्मित किए जाने के लिये दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करना है। प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल लागत राशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए पहले ही मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

सत्य का असर

सत्य का असर समाचार पत्र

16,06,2024 jksingh hardoi agmail com मोबाइल नंबर 9956834016

वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह पटेल / सत्य का असर समाचार पत्र 01

कानपुर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने "जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र" (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर किए हस्ताक्षर,

पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20%मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। गन्ना आधारित फीड-स्टाक की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश में इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्के को एक प्रमुख फीडस्टॉक के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

कानपुर एनएसआई की रिपोर्ट

सत्य का असर समाचार पत्र

यह "समझौता ज्ञापन" तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर, दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है।

यह 'समझौता ज्ञापन', नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने, कार्बन डाइआक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुये जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता/कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा। (अखिलेश कुमार पांडे) मुख्य अभिकल्पक मो. 9984364957

हस्ताक्षर करती कानपुर एनएसआई निदेशक डॉ सीमा परोहा, समझौता ज्ञापन" तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित

[illegible]

The Pioneer

NSI, IIT-K sign MoU

PIONEER NEWS SERVICE ■ KANPUR

The National Sugar Institute, (NSI), Kanpur, and Indian Institute of Technology, Kanpur signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Saturday to establish a Centre of Excellence for Biofuels. The MoU was signed in the presence of Ashwani Srivastava, Joint Secretary (Sugar), Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India; Professor Manindra Agrawal, Director of IIT Kanpur and Professor Seema Paroha, Director of the NSI. Professor Rajeev Jindal and Debopam Das from IIT Kanpur and Vinay Kumar, Anup Kumar Kanojia and Dr R Anantalakshmi from the NSI were also present. Under this MoU, NSI, Kanpur, and IIT-Kanpur will collaborate on joint projects to enhance the effectiveness and sustainability of biofuel production in India through advanced research and development and adoption of cutting-edge technologies. In the first phase, proposals will be solicited from the NSI and IIT Kanpur. In the subsequent phase, proposals will also be invited from centrally and state-funded institutions/universities and other organisations/industries. This collaborative research will include comprehensive studies on increasing the production of ethanol, methanol, bio-CNG, aviation fuel, green hydrogen etc. from biomass and renewable energy sources. The MoU is signed for three years and can be extended based on mutual agreement and review by both institutions upon its completion. Prof Manindra Agrawal highlighted that the NSI has been working in this field for nearly 60 years, understanding market conditions and technical requirements well. Similarly, IIT Kanpur has fundamental capabilities in chemistry and related technologies. The aim is to integrate the strength of both institutions to establish state-of-the-art centre that will help India take a leadership position in the biofuels sector. Ashwani Srivastava, Joint Secretary (Sugar), Government of India mentioned that National Biofuel Policy, 2018 ,allows the use of surplus food grains for ethanol production and the production of ethanol from various sugarcane-based feed stocks. Under the Ethanol Blended Petrol (EBP) programme, the government has set a target to achieve 20 per cent ethanol blending with petrol by 2025. Considering the limited availability of sugarcane-based feed stocks, the government is promoting maize as a major feedstock for increasing ethanol production in the country. Besides ethanol, the government is also focusing on the utilisation of other by-products of sugarcane, such as potash derived from molasses as a fertiliser Compressed Bio Gas (CBG) as a green renewable automotive fuel under the concept of waste-to-wealth. By focusing on the sustainability of biofuels, the government's efforts will help reduce the import bill for crude oil and decrease dependence on imported fossil fuels, contributing to the goal of an energy-independent India. The centre will support biofuel innovation while ensuring security and sustainability. He extended his best wishes for the joint research work between the two esteemed institutions.

NSI Kanpur and IIT Kanpur signed an MoU on Saturday

Director of NSI, Professor Seema Paroha, announced that a dedicated building equipped with all necessary equipment, pilot plants and a central facility with a state-of-the-art laboratory for this specific task will be established on the institute's campus for the Centre of Excellence. The total cost will be provided by the ministry, which has already given administrative approval. This MoU will pave the way for the production of advanced, sustainable and high-quality biofuels by developing innovative technologies, optimising existing processes and demonstrating the feasibility of biofuel technology through the establishment of pilot projects. Ultimately, this will help preserve energy supply, reduce unnecessary carbon dioxide emissions, protect the climate and decrease dependency on biofuels and crude oil imports.

BREAKTHROUGH: A team of scientists from the Indian Institute of Technology Kanpur, Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA) Pune, and Ashoka University has made a significant breakthrough using data from India's first astronomical observatory, AstroSat. Their research reveals new insights into the internal structure of neutron stars, some of the densest objects in the universe.

आईआईटी और शर्करा संस्थान के बीच जैव ईंधन पर तीन वर्षीय एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

कानपुर-(दीपक गौड़) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शनिवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक महत्वपूर्ण एवं सम-सामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र के समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किये एमओयू पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की गरिमामई उपस्थिति में संपन्न हुए समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश में बायो फ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभाव शीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रस्ताव लिये जायेंगे अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा यह तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इस संबध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20नमिश्रण का लक्ष्य तय किया है प्रोफेसर सीमा परोहा निदेशक शर्करा संस्थान ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह 'समझौता ज्ञापन', नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंतत: ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने हेतु कार्बन-डाई-ऑक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुए जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता, कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर अनंत लक्ष्मी उपस्थित रहे

अमृत विचार

हुआ करार | जैव ईंधन के उत्पादन में आईआईटी और एनएसआई मिलकर करेंगे काम

बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बॉयो फ्यूल्स

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

एनएसआई में एमओयू के दौरान मौजूद आईआईटी के निदेशक प्रो . मणींद्र अग्रवाल, संयुक्त सचिव (शर्करा) अश्वनी श्रीवास्तव एवं एनएसआई निदेशक प्रो . सीमा परोहा ।

अमृत विचार। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स का निर्माण किया जाएगा। इसमें पेट्रोल के विकल्प के रूप में इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ाने और जैव ईंधन के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए एनएसआई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने हाथ मिलाया है। शनिवार को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (शर्करा) अश्वनी श्रीवास्तव, आईआईटी के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल और एनएसआई की निदेशक प्रो. सीमा परोहा की उपस्थिति में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। तीन वर्ष के लिए हुए समझौते के तहत दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ देश में बायोफ्यूल उत्पादन की बेहतर प्रभावशीलता के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान के साथ ही अत्याधुनिक तकनीकी विकास के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे। आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि एनएसआई बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए इस क्षेत्र में करीब 60 वर्षों से कार्यरत है, जबकि आईआईटी के पास रसायन एवं अन्य संबंधित तकनीकी में आधारभूत क्षमता है। दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करके जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाना है। एनएसआई की निदेशक प्रोफेसर सीमा परोहा ने बताया कि कैंपस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स में सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरणों की सुविधा से युक्त आधुनिक प्रयोगशाला होगी। इसकी लागत के लिए मंत्रालय स्वीकृति प्रदान कर चुका है। आईआईटी के साथ यह 'समझौता' नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुए उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने, कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन को कम कर जलवायु को संरक्षित करेगा।

अगले वर्ष पेट्रोल के साथ 20 फीसद इथेनॉल मिश्रण

कानपुर। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20 फीसद मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। गन्ना आधारित फीड स्टाक की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश में इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के को एक प्रमुख फीड स्टॉक के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बात भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (शर्करा) अश्वनी श्रीवास्तव ने एनएसआई में कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल उत्पादन के साथ अन्य अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। जैव ईंधन की दीर्घकालिकता को ध्यान में रखते हुए उन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने से न केवल कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी बल्कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम होगी।

देश-विदेश | भोपाल, शनिवार 15 जून 2024 | 07

जैव ईंधन पर शर्करा संस्थान और आईआईटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हुएं हस्ताक्षर

पेट्रोल के वैकल्पिक स्त्रोतों यथा-इथेनाल आदि की उपलब्धता बढ़ाने, जैव ईंधन के उत्पादन पर जोर देने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं होंगी तैयार

आईआईटी और शर्करा संस्थान के बीच जैव ईंधन पर तीन वर्षीय एमओयू

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शनिवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र के समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

एमओयू पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रोफेसर सीमा परोहा निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुए। समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश में बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे'। इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रस्ताव लिये जायेंगे। अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों / विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों / उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे। सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यह तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर, दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है। प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इस संबंध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है। अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए, अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20%मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर. अनंतलक्ष्मी उपस्थित रहे।

दैनिक जागरण

तैयार करेंगे अगली पीढ़ी की जैव ईंधन तकनीक

जासं, कानपुर : राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और आइआइटी कानपुर ने जैव ईंधन तकनीक विकास के लिए हाथ मिलाया है। शनिवार को आइआइटी निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल और एनएसआइ की ओर से भारत सरकार के संयुक्त सचिव (शर्करा) अश्वनी श्रीवास्तव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइआइटी निदेशक ने बताया कि संस्थान के पास पहले से तकनीकी दक्षता है अब एनएसआइ के शोध निष्कर्षों का प्रयोग कर अगली पीढ़ी की जैव ईंधन तैयार करेंगे।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू के बाद एनएसआइ में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन अतिथियों ने किया। संयुक्त सचिव अश्वनी श्रीवास्तव ने बताया कि एथेनाल उत्पादन में भारत ने लक्ष्यों को पूरा किया है। इस साल 15 हजार करोड़ लीटर एथेनाल का उत्पादन हुआ है। अगले साल इसे 17 हजार करोड़ लीटर करने का लक्ष्य है। एनएसआइ निदेशक प्रो. सीमा परोहा ने बताया कि केंद्र में बायोमास से एथेनाल, मीथेनाल, सीबीजी, वायुयान ईंधन, ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण पर काम किया जाएगा।

आइआइटी निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल (बाएं) व भारत सरकार के संयुक्त सचिव अश्वनी श्रीवास्तव (मध्य में) साथ में एनएसआइ निदेशक प्रो. सीमा परोहा (दाएं) ● प्रबंधन

उत्कृष्टता केंद्र से जुड़े विज्ञानी

निगरानी और कामकाज को पूरा करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें एनएसआइ निदेशक प्रो. सीमा परोहा, आइआइटी के प्रो. राजीव जिंदल, प्रो. देवोपम दास, एनएसआइ के डा. विनय कुमार, डा. अनूप कुमार कनौजिया, डा. अनंतलक्ष्मी रघुनाथन शामिल है।

सच की अहमियत

आईआईटी और शर्करा संस्थान के बीच जैव ईंधन पर तीन वर्षीय एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

पंकज अवस्थी, सच की अहमियत

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शनिवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक महत्वपूर्ण एवं सम-सामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र के समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किये एमओयू पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की गरिमामई उपस्थिति में संपन्न हुए समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश में बायो फ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रस्ताव लिये जायेंगे अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा यह तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इस संबंध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20%मिश्रण का लक्ष्य तय किया है प्रोफेसर सीमा परोहा निदेशक शर्करा संस्थान ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह 'समझौता ज्ञापन', नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यावहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने हेतु कार्बन-डाई-ऑक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुए जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता, कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर. अनंत लक्ष्मी उपस्थित रहे।

चेतना समाचार

जैव ईंधन के उत्पादन पर जोर देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं होगी तैयार -अश्वनी श्रीवास्तव

चेतना समाचार सेवा

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने शनिवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में एक अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर की गरिमामई उपस्थिति में संपन्न हुए इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया

एवं डॉ. आर. अनंत लक्ष्मी उपस्थित रहे समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर देश में बायो फ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु, उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से प्रस्ताव लिये जायेंगे अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों, उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे

अमर भारती

आईआईटी व शर्करा संस्थान के बीच जैव ईंधन पर हुआ एमओयू

अमर भारती ब्यूरो

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शनिवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र के समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किये। एमओयू पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुए।

समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश में बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे'। इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रस्ताव लिये जायेंगे। अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों / विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों / उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे। सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यह तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर, दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है।

प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इस संबध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है। अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20त्नमिश्रण का लक्ष्य तय किया है। प्रोफेसर सीमा परोहा निदेशक शर्करा संस्थान ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह 'समझौता ज्ञापन', नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने, कार्बन डाइआक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुये जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता/कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा।इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर. अनंतलक्ष्मी उपस्थित रहे।

भोर वैभव

आईआईटी और शर्करा संस्थान के बीच जैव ईंधन पर तीन वर्षीय एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

भोर वैभव । दीपक गौड़

कानपुर । राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शनिवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक महत्वपूर्ण एवं सम-सामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र के समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किये एमओयू पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की गरिमामई उपस्थिति में संपन्न हुए समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश में बायो फ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभाव शीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रस्ताव लिये जायेंगे अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगटनों उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा यह तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इस संबध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20%मिश्रण का लक्ष्य तय किया है प्रोफेसर सीमा परोहा निदेशक शर्करा संस्थान ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह ह्वसमझौता ज्ञापनह्न, नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने हेतु कार्बन-डाई-ऑक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुए जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता, कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर. अनंत लक्ष्मी उपस्थित रहे

जैव ईंधन पर शर्करा संस्थान और आईआईटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हुएं हस्ताक्षर

आज का कानपुर

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने 15 जून, 2024 को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में एक अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय- जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुए। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर. अनंतलक्ष्मी उपस्थित रहे। समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर 'देश में बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु, उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे'। इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से प्रस्ताव लिये जायेंगे। अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों / विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों / उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे। इस सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

यह समझौता ज्ञापन तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर, दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है।

प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, आईआईटी कानपुर ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर इस संबंध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है। इसी प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पास रसायन एवं अन्य संबंधित तकनीकी में आधारभूत क्षमता है। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहयोग करने के लिए अत्याधुनिक विशिष्ट केंद्र निर्मित किए जाने हेतु दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करना है। अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। गन्ना आधारित फीड-स्टाक की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश में इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्के को एक प्रमुख फीडस्टॉक के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

इथेनॉल के अलावा, गन्ने के अन्य उप उत्पादों जैसे मौलैसेस से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) के उर्वरक, संपीड़ित बायो-गैस(सीबीजी) के रूप में प्रयोग के लिए, जिसे हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, सरकार इनके उपयोग को बढ़ावा देकर वेस्ट से वैल्थ (व्यर्थ से अर्थ) की संकल्पना पर भी ध्यान दे रही है।जैव ईंधन की दीर्घकालिकता को ध्यान में रखते हुए उन पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने से न केवल कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी बल्कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता भी कम होगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा। केंद्र सुरक्षा एवं दीर्घकालिकता सुनिश्चित करते हुए जैव ईंधन नवाचार का समर्थन करेगा। उन्होंने दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच संयुक्त शोध कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएँ दीं। प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण, पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल लागत राशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए पहले ही मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह 'समझौता ज्ञापन', नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु पायलट परियोजनाओं को स्थापित करते हुये उन्नत, दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करने, कार्बन डाइआक्साइड के अनावश्यक उत्सर्जन को कम करते हुये जलवायु को संरक्षित करने और जैव ईंधन पर निर्भरता/कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायक होगा।

एन एस आई वा आईआईटी जैव ईंधन की तनिक पर कार्य करेगा

ब्यूरो चीफ विशाल सैनी

कानपुर-राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और आइआइटी कानपुर ने जैव ईंधन तकनीक विकास के लिए हाथ मिलाया है। आइआइटी निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल और एनएसआइ की ओर से भारत सरकार के संयुक्त सचिव (शर्करा) अश्वनी श्रीवास्तव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइआइटी निदेशक ने बताया कि संस्थान के पास पहले से तकनीकी दक्षता है अब एनएसआइ के शोध निष्कर्षों का प्रयोग कर अगली पीढ़ी की जैव ईंधन तैयार करेंगे। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू के बाद एनएसआइ में स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन अतिथियों ने किया। संयुक्त सचिव अश्वनी श्रीवास्तव ने बताया कि एथेनाल उत्पादन में भारत ने लक्ष्यों को पूरा किया है। इस साल 15 हजार करोड़ लीटर एथेनाल का उत्पादन हुआ है। अगले साल इसे 17 हजार करोड़ लीटर करने का लक्ष्य है। प्रोफेसर सीमा परोहा निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने बताया कि सभी आवश्यक उपकरण,पायलट प्लांट और यंत्रों के साथ केन्द्रीय उपकरण की सुविधा से युक्त, एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला सहित इस विशिष्ट कार्य के लिए एक समर्पित भवन,सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसकी कुल लागत राशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी,जिसके लिए पहले ही मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

आईआईटी और शर्करा संस्थान के बीच

जैव ईंधन पर तीन वर्ष का एमओयू

कानपुर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शनिवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में एक महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र के समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किये। एमओयू पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रोफेसर सीमा परोहा निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुए।

समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश में बायोफ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे। इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रस्ताव लिये जायेंगे। अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों ध् विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनो/उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे। सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से ईथेनाल, मीथेनाल, बायो.सीएनजी, विएशन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यह तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है। प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक आईआईटी ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान इस संबध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भलीभांति समझते हुएए इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है। अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव शर्करा ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ आर अनंतलक्ष्मी उपस्थित रहे।

जैव ईंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र हेतु राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और आईआईटी कानपुर में समझौता

ग्रामीण सुबह- कानपुर- राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI), कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर ने 15 जून, 2024 को NSI कानपुर में जैव ईंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्री अश्वनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक, IIT कानपुर, और प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक, NSI कानपुर उपस्थित थे। इस महत्वपूर्ण समारोह में प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास, श्री विनय कुमार, श्री अनूप कुमार कनौजिया, और डॉ. आर. अनंतलक्ष्मी भी शामिल थे।

समझौते के अंतर्गत, दोनों संस्थान संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करेंगे, जो जैव ईंधन उत्पादन की प्रभावशीलता और दीर्घकालिकता को बढ़ावा देंगे। इस सहयोग के पहले चरण में, NSI और IIT कानपुर से प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। अगले चरण में, केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा समर्थित संस्थानों, विश्वविद्यालयों, और उद्योगों से भी प्रस्ताव लिए जाएंगे।

इस शोध में बायोमास से एथेनॉल, मीथेनॉल, बायो-सीएनजी, एविएशन फ्यूल, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जैव ईंधनों के उत्पादन पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन तीन वर्षों के लिए मान्य है, जिसे अवधि पूरी होने पर समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि NSI और IIT कानपुर की संयुक्त शक्ति जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहायक होगी। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से न केवल कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती होगी, बल्कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त होगा। प्रोफेसर परोहा ने बताया कि इस परियोजना के लिए एक समर्पित भवन, अत्याधुनिक प्रयोगशाला और उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जिसकी कुल लागत राशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

यह समझौता जैव ईंधन की नवाचारी तकनीकों के विकास, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुकूलन, और उच्च गुणवत्ता वाले जैव ईंधन के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को संरक्षित करते हुए जलवायु को संरक्षित किया जा सकेगा।

अमर उजाला

नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट बनेगा जैव ईंधन उत्कृष्टता केंद्र

आईआईटी और एनएसआई हवाई जहाज के ईंधन, बॉयो गैस आदि पर मिलकर करेंगे काम

[illegible]

[illegible]

इथेनॉल के प्रमुख फीड स्टाक के लिए मक्का को बढ़ाया

[illegible]

जन मत टूडे

जैव ईंधन पर शर्करा संस्थान व आईआईटी के बीच समझौता

दीपक गौड़ (जनमत टूडे)

कानपुर: राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने 15 जून, 2024 को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में एक अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय "जैव ईंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र" (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल्स) के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये "समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर अश्वनी श्रीवास्तव संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर एवं प्रोफेसर सीमा परोहा, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर की गरिमामई उपस्थिति में संपन्न हुए इस अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रोफेसर राजीव जिंदल, प्रोफेसर देबोपम दास तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के विनय कुमार, अनूप कुमार कनौजिया एवं डॉ. आर. अनंत लक्ष्मी उपस्थित रहे।

"समझौता ज्ञापन" के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर "देश में बायो फ्यूल उत्पादन का बेहतर प्रभाव शीलता और दीर्घकालिकता के साथ संवर्धन करने हेतु, उत्कृष्ट अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकी के विकास तथा उसको आत्मसात करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं में कार्य करेंगे' इस समझौता ज्ञापन के प्रथम चरण में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से प्रस्ताव लिये जायेंगे अगले चरण में केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों, उद्योगों से भी प्रस्ताव लिये जाएंगे इस सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास से इथेनाल, मीथेनाल, बायो सीएनजी, एविएशन फ्यूल (विमानीय ईंधन), ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा यह "समझौता ज्ञापन" तीन वर्ष के लिए हस्ताक्षरित है, जिसके पूर्ण होने पर, दोनों संस्थानों की समीक्षा और आपसी सहमति के आधार पर अवधि बढ़ायी जा सकती है प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल, निदेशक आईआईटी कानपुर ने बताया कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर इस संबध में बाजारगत स्थिति एवं तकनीकी आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हुए, इस क्षेत्र में लगभग 60 वर्षों से कार्यरत है इसी प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पास रसायन एवं अन्य संबंधित तकनीकी में आधारभूत क्षमता है इसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व की स्थिति में लाने में सहयोग करने के लिए अत्याधुनिक विशिष्ट केंद्र निर्मित किए जाने हेतु दोनों संस्थाओं की शक्ति को एकीकृत करना है।

अश्विनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (शर्करा), भारत सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 विभिन्न गन्ना आधारित फीड स्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन के साथ-साथ, इथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देती है पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।

DIGITAL NEWS

जैव ईंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र हेतु राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और आईआईटी कानपुर में समझौता

एन एस आई और आई आई टी के बीच एम ओ यू का हुआ करार।

कानपुर में एक अति महत्वपूर्ण एवं समसामयिक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

Report,NSI & IIT Kanpur signed MOU/centre of Excellence for Biofuels

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के द्वारा दो संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम रखा गया

एनएसआई के साथ जैव ईंधन पर अनुसंधान करेगा कानपुर आईआईटी

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और IIT ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो फ्यूल के समझौते पर किए हस्ताक्षर

कानपुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फाॅर बॉयोफ्यूल्स, आईआईटी के एक्सपर्ट करेंगे मदद